इस्पात मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1208

7 मार्च, 2013 को उत्तर के लिए

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सुधार लाने के लिए योजना

1208. श्री धीरज प्रसाद साहू:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इस्पात मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को लाभप्रद बनाने के लिए कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) घाटे में चल रहे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के नाम क्या हैं, और उनमें कितनी राशि का घाटा हुआ तथा इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या इन घाटे पर चल रहे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को बन्द करने के लिए कोई कार्रवाई की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

इस्पात मंत्री श्री बेनी प्रसाद वर्मा

(क) और (ख): इस्पात मंत्रालय के अधीन आने वाले प्रत्येक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम से यह अपेक्षा की जाती है कि वह प्रतिस्पर्धा और वाणिज्यिक दृष्टि से सक्षम बने रहने के लिए आवश्यक उपाय करे। तदनुसार, इस्पात मंत्रालय के अधीन आने वाले सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों से यह अपेक्षा की गई है कि वे वार्षिक वास्तविक तथा वित्तीय लक्ष्यों का उल्लेख करते हुए सरकार के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) संपन्न करें। इसी आधार पर इस्पात मंत्रालय द्वारा समय-समय पर उनके कार्य-निष्पादन की समीक्षा की जाती है और लोक उद्यम विभाग द्वारा वार्षिक आधार पर अंतिम रूप से उनका मूल्यांकन करके उन्हें ग्रेड दिया जाता है।

(ग): इस समय इस्पात मंत्रालय के अधीन घाटे में चल रहे दो सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम अर्थात हिंदुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड (एचएससीएल) और दि बिसरा स्टोन लाइम कंपनी लिमिटेड (बीएसएलसी) हैं जिनका कुल संचित घाटा लगभग 1630 करोड़ रूपये है। यह घाटा निम्नलिखित कारणों से है- श्रम शक्ति की अनियोजित भर्ती, इस्पात क्षेत्र में मंदी, खनन उपकरणों की अनुपलब्धता, अनियमित बाजार मांग, आदि।

(घ): जी, नहीं।

(ड.): प्रश्न नहीं उठता।

****